15 दिसंबर तक पूरा होगा अयोध्या एयरपोर्ट का कार्य

मुख्यमंत्री योगी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व वीके सिंह के साथ किया निरीक्षण

- सीएम ने कहा-जल्द कराया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी से उद्घाटन
- सिंधिया बोले-सांस्कृतिक विरासत को एयरपोर्ट पर उभारने का प्रयास

अयोध्या में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह ने रामलला के दर्शन-पूजन के साथ निर्माणाधीन राम मंदिर का अवलोकन किया • प्रेट्र

जागरण संवाददाता, अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह शनिवार को रामनगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन श्रीराम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री जो भी तिथि निर्धारित करेंगे, उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या में पहले मात्र 178 एकड़ जमीन हवाई अड्डे के लिए उपलब्ध थी। इस पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई, जिस पर एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया निर्माण कर रही है। श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने का लक्ष्य साकार होने वाला है।

रामलला के दर्शन को भावनात्मक क्षण बताते हुए सिंधिया ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करना सौभाग्य का क्षण है। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। अयोध्या का एयरपोर्ट भी सामान्य नहीं है। यहां पर सांस्कृतिक विरासत को परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले डेढ़ माह में देश में करीब आठ और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

हनुमानगढ़ी में किए दर्शन मंदिर निर्माण का अवलोकन

मुख्यमंत्री योगी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने रामनगरी में आस्था भी अर्पित की। उन्होंने प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी में विराजे बजरंगबली का दर्शन-पूजन करने के बाद रामलला का दर्शन-पूजन किया। निर्माणाधीन राम मंदिर का भी अवलोकन किया। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय, ट्रस्ट के सदस्य एवं अयोध्या राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्र मोहन मिश्र, ट्रस्ट के अन्य सदस्य डा. अनिल मिश्र, विहिप के केंद्रीय मंत्री गोपालजी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सड़क दुर्घटनाओं से मौतों को रोकना बड़ी चुनौती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दो वर्षों में प्रदेश में 24 हजार से कम लोगों की मृत्यु हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 20 से 22 हजार लोग जान गंवाते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से जान गंवाने वालों के पूरे परिवार पर वज्रपात होता है। सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को रोकना बड़ी चुनौती है। थोड़े प्रयास से अमूल्य जान बचाई जा सकती है। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की ओर से खरीदे गए 38 स्कार्पियो इंटरसेप्टर वाहनों, सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता पैदा करने के लिए 12 प्रचार वाहनों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाई जाने वाली 50 बीएस-6 बसों को शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा में स्थापित किये गए ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (डीटीटीआइ) के संचालन के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और परिवहन विभाग के बीच अनुबंध हुआ।

परिवहन के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक युवाओं का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव तक बस सेवा पहुंचाने के लिए प्रदेश में दो लाख इलेक्ट्रिक बसों का बाजार उपलब्ध है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपये अनुदान दे रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के खातों में भेजी रकम

मुख्यमंत्री ने 4110 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के खाते में राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 13.11 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का आनलाइन हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 वाहन स्वामियों को चेक भेंट किए। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में भी बताया।

महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए अनुबंध

महिला चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उप्र कौशल विकास मिशन के बीच भी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनुबंध ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने का माध्यम बनेगा।